न्याय के साथ

विकास यात्रा

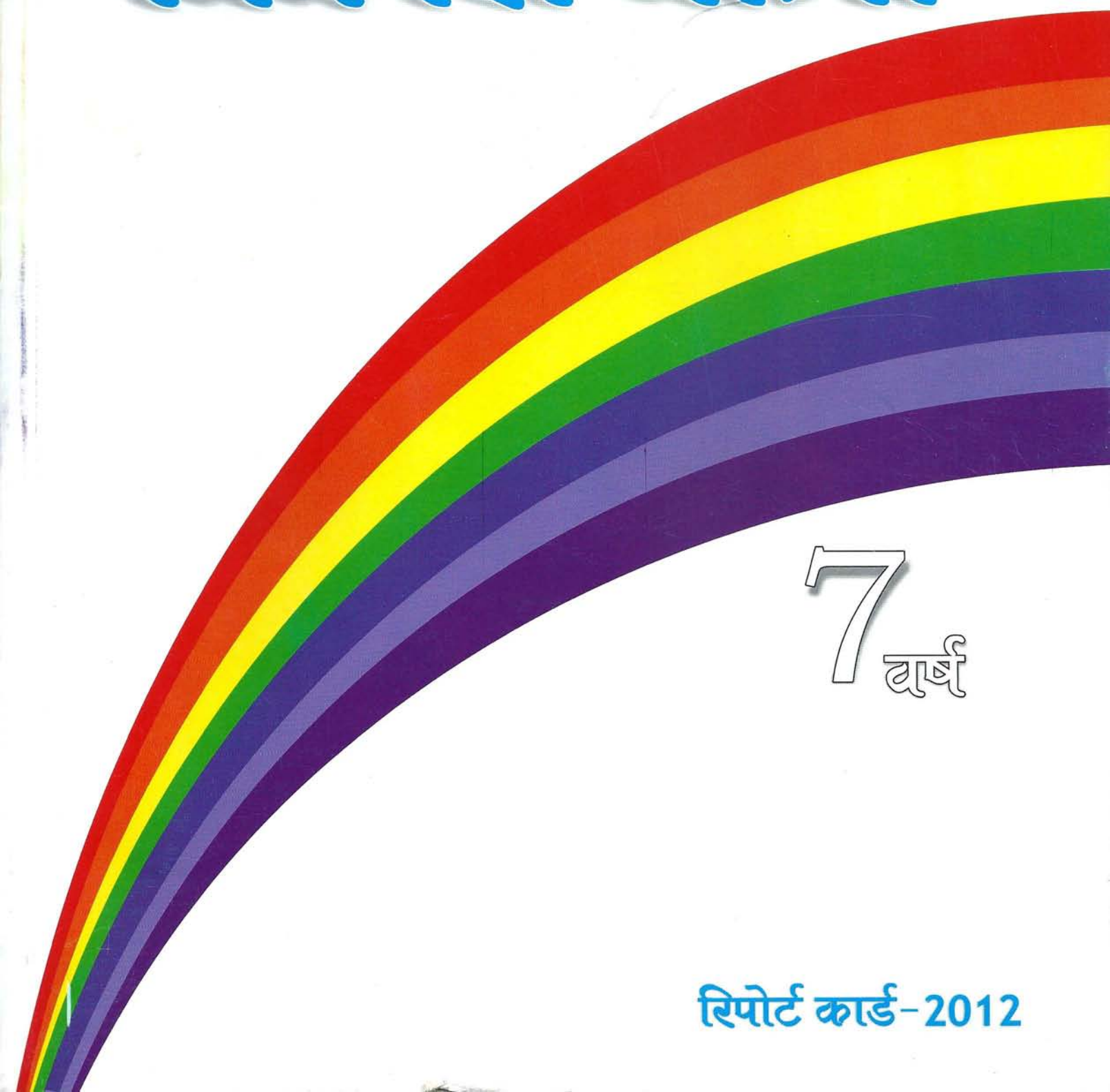

7 वर्ष

रिपोर्ट कार्ड-2012

बिजली

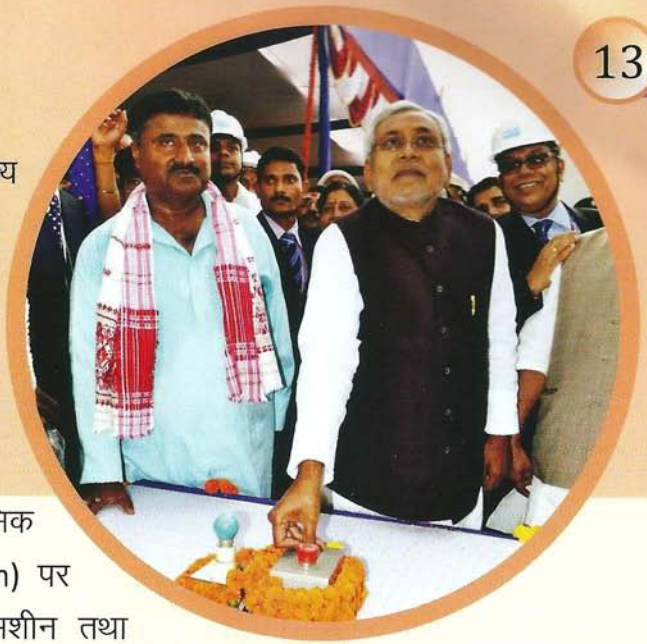

- राज्य के ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को पाँच कम्पनियों यथाः एक होल्डिंग कम्पनी, एक उत्पादन, एक संचरण कम्पनी तथा दो वितरण कम्पनी में पुनर्गठन किया गया ।
- विशेष अभियान चलाकर बिजली बोर्ड ने कुल 3,50,000 नये विद्युत कनेक्शन दिये।
- उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपभोक्ताओं का मासिक विपत्र बोर्ड के वेबसाईट (www.bseb.bih.nic.in) पर उपलब्ध। ए॰टी॰एम॰, सहज, वसुधा केन्द्र, एटीपी मशीन तथा नेट–बैंकिंग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विपत्र के भुगतान के बहुविधिक विकल्पों को अपनाने की प्रक्रिया प्रारंभ।
- क्षतिग्रस्त मीटरवाले उपभोक्ताओं तथा मीटरविहीन उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर अधिष्ठापन / बदलने का व्यापक अभियान प्रारंभ।
- बिजली विपत्र, ट्रांसफार्मर बदलने आदि से संबंधित मामलों के लिए बोर्ड में हेल्पलाइन नं॰ – 9430807821 कार्यरत।
- कृषि रोड मैप के अन्तर्गत इन्द्रधनुषी क्रांति के लिए बिजली की उपलब्धता एवं कृषि कार्यों के लिए डेडिकेटेड फीडर हेतु सर्वे का कार्य प्रगति पर। पटना जिला Pilot Project के रुप में चयनित। पटना जिला के नौबतपुर प्रखण्ड का सर्वे कार्य पूर्ण।
- पेसू (पटना) क्षेत्र में न्यू कैपिटल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के ओवरहेड तारों को भूमिगत केबुल में परिवर्तित करने का कार्य पूर्ण।
- पेसू के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था।
- पटना शहर में डेडिकेटेड फीडर द्वारा भूमिगत केबुल से कुल 73 अद्द पेयजल पम्पों का ऊर्जान्वयन।

विकसित होता ऊर्जा प्रक्षेत्र

- राज्य सरकार के प्रयास से Barh STPS Stage - I से 523 मेगावाट तथा Stage - II से 660 मेगावाट बिजली बिहार को आवंटित।
- मुजफ्फरपुर में 2 × 195 मेगावाट इकाई के निर्माण का कार्य प्रगति पर। इसके अतिरिक्त 195 मेगावाट की एक अतिरिक्त इकाई प्रस्तावित।
- नबीनगर में 3× 600 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु आवश्यक जमीन का भौतिक अधिग्रहण तथा समतलीकरण का कार्य प्रगति पर। Stage - II के अन्तर्गत 3 × 600 मेगावाट प्लांट लगाने की योजना है।
- बरौनी में 2 × 250 मेगावाट इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार के प्रयास से कोयला मंत्रालय द्वारा Tapering Coal Linkage हेतु सहमति के पश्चात् PFC द्वारा ऋण विमुक्ति की कार्रवाई।
- फेज II प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कजरा, पीरपैंती एवं चौसा (प्रत्येक 2 × 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट) में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के तहत आवश्यक भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर। चौसा एवं कजरा में स्थापित होनेवाली 2 × 660 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित प्लांटो को क्रमशः मेमर्स सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा मेसर्स एन॰एच॰पी॰सी॰ लिमिटेड को स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इन दोनों परियोजनाओं से कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत बिजली बिहार राज्य को प्राप्त होगा।
- राज्य सरकार के प्रयास से DVC से 100 मेगावाट बिजली आवंटित।
- NABARD फेज XI में टर्न–की आधार पर 907 राजकीय नलकूपों का ऊर्जान्वयन।
- बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में 5 जिलों के 10 प्रखंडों में 560 अद्द सोलर पम्प अधिष्ठापन की योजना स्वीकृत।

- बायोमास गैसीफायरों का अधिष्ठापन कर गाँवों के समूहों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 50 बायोमास गैसीफायरों का अधिष्ठापन कर विद्युत उत्पादन।

न्याय के साथ
विकास यात्रा 7 वर्ष

- थारू विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिले के थारु बाहुल्य गाँवों में सौर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया गया।
- पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत विक्रमशिला खुदाई स्थल, कहलगाँव, भागलपुर में राज्य सरकार द्वारा 75 अद्द सौर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित।
- ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राजभवन, सभी सचिवालय भवनों, विधान मंडल भवन, श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र तथा उद्योग भवन सहित 16 भवनों में ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न।
- सुपौल जिलान्तर्गत कटैया जल विद्युत परियोजना (19.2 MW) का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया।
- पटना कैनाल पर स्थित डेहरा एवं सिपहा परियोजना (2 MW) का निर्माण कार्य प्रारंभ।
- मधेपुरा जिलान्तर्गत आरारघाट (4 × 1.75 MW) जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु ऋण स्वीकृत। निर्माण कार्य प्रारंभ।
- बरौनी एवं मुजफ्फरपुर की चारों 110 मेगावाट की इकाईयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य भेल द्वारा किया जा रहा है, जिसे क्रमशः दिसम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।
- केन्द्रीय प्रक्षेत्र से आवंटित बिजली की उपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए दिसम्बर 2015 तक के लिए 200 मेगावाट बिजली क्रय की जा रही है।
- बरौनी में वर्तमान आधारभूत संरचना के अन्तर्गत 1X250 मेगावाट की नई यूनिट की स्थापना हेतु वाह्य संपोषित योजना के तहत सकारात्मक पहल की जा रही है।

- केस – I बिडिंग के अन्तर्गत 1010 मेगावाट विद्युत क्रय हेतु PPA हस्ताक्षरित, जो क्रमिक रूप से जुलाई, 2014 से उपलब्ध होगा।
- संचरण, उपसंचरण एवं वितरण प्रणाली में क्षमता विस्तार एवं सृदृढ़ीकरण के लिए विशेष कदम उठाया गया है। बी0आर0जी0एफ0 के अंतर्गत उपसंचरण प्रणाली के सृदृढ़ीकरण की योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा शेष कार्य मार्च 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है। संचरण के क्षेत्र में राज्य सरकार ए0डी0बी0 से ऋण द्वारा तीन ग्रीड उपकेन्द्रों धनहा (बेतिया), गंगवारा (दरभंगा), पुसौली (कैमूर) एवं संबंधित

संचरण लाईन के निर्माण करवा रही है। इसके अलावा 5 नये ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण (टेहटा, इमामगंज, एकमा, करबिगहिया एवं जनदाहा) राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 157.66 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है।

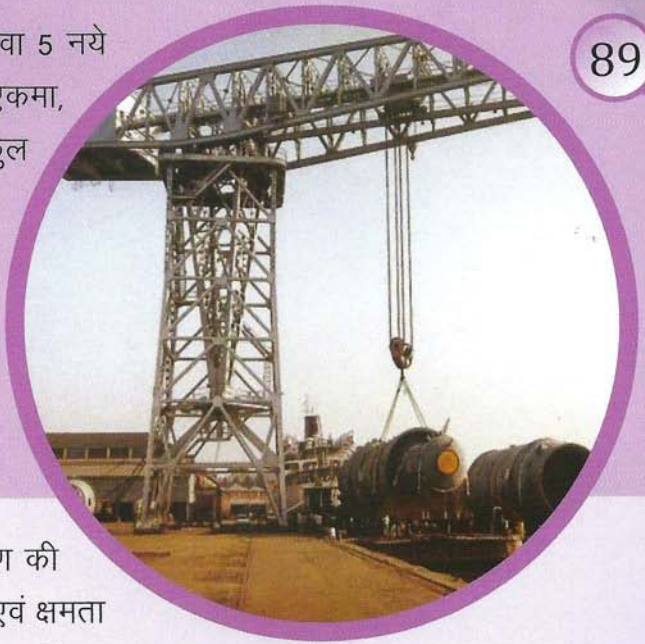

- आर0ए0पी0डी0आर0पी0 (Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme) योजना के तहत 64 शहरों में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वृद्धि का कार्य 1200 करोड़ की लागत पर कराया जा रहा है।
- वितरण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ए0डी0बी0 के ऋण की मदद से 7 शहरों के वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वृद्धि का कार्य ₹ 708 करोड़ की लागत पर कराया जा रहा है।
- पुनरीक्षित राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत कुल ₹ 3130 करोड़ की लागत से 11 जिलों के विभिन्न गाँवों एवं बसावट में पूर्णरूप से विद्युतीकरण हेतु कार्यादेश अंतिम चरण में।